प्रो० अजित कुमार मेहता : पैसा तो आप आलरेडी वसूल रहे हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह डयूटी नई नहीं है, आपने खुद भी कहा है कि 1 रु० की ड्यूटी लगाई जाती है, उसके लिये पार्लियामेंट पहले एक्ट पास कर चुके हैं, अब इस नये बिल के जरिये हम 1 रु० से बढ़ाकर 5 रु० तक डयूटी लगाने का इख्तियार पार्लियामेंट से मांग रहे हैं।

आपको जो यह खतरा है, वह बिल्कुल निराधार है कि जब यह ड्यूटी लगेगी, तो वह वस्तु गुम हो जाएगी। डयूटी निकले हुए तेल के ऊपर लगेगी। जब तेल निकल जाएगा और उस पर डयूटी लगेगी, तो वह गुम नहीं होगा बल्कि लिखित में आ जाएगा और यह पता लग जाएगा कि कितना तेल पैदा हुआ है। इसलिए बाजार से उसके गुम होने का सवाल पैदा नहीं होता है बल्कि उसको कन्ट्रोल करने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट के लिए मार्केट के अन्दर उसको ठीक तरीके से पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को आसानी होगी क्योंकि सारी चीज पर ड्यूटी लगने के बाद जितनी पैदावार होती है, उसको पता लग जाता है। जो डर आपने जाहिर किया है, उसका कोई बेसिस नहीं है और इस वक्त इस बात का आश्वासन देना मुनासिब नहीं है। जब अभी ऐसी कोई ड्यूटी लगी है और न कोई पैसा वसूल हुआ है। आयलसीड्स के डेवलपमेंट के लिए, किसानों को अच्छा बीज देने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए और इस इंडस्ट्री को सुविधाएं देने के लिए अभी काफी गुंजाइश है क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर 600-700 करोड़ रुपये का वेजीटेबिल आयल इम्पोर्ट होता है हर साल और अभी जो हमारे देश में इसकी कमी है, इसको कैसे पूरा किया जाए, आप इस बात का ध्यान रखिये और इसके लिए हमारी मदद कीजिए न कि यह कि ड्यूटी लगने के पहले ही आप यह चाहते हैं कि हम यह घोषणा कर दें कि ड्यूटी बन्द कर दी गई। हिन्दुस्तान में अगर आयल प्रोडक्शन काफी होगा और तेल काफी हिन्दुस्तान के अन्दर पैदा होगा, तो अरबों रुपया यहां पर जमा हो जाएगा। यह तो थोड़ी-सी रकम आने वाली है और मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि यह रकम सिर्फ आयलसीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और इन्डस्ट्री की सहायता के लिये ही इस्तेमाल की जाएगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the levy and collection of a cess on vegetable oils for the development of the oilseeds industry and the vegetable oils industry and for matters connected therewith."

The motion was adopted

RAO BIRENDRA SINGH : I introduce the Bill.

NATIONAL OILSEEDS AND VEGETABLE OILS DEVELOPMENT BOARD BILL.*

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the development under the control of the Union of the oilseeds industry and the vegetable oils industry and for matters connected therewith.

**Published in Gazette of India extraordinary, Part II, Section 2 dt. 3-5-83.

MR. DEPUTY-SPEAKER ; The question is :-

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the development under the control of the Union of the oilseeds industry and the vegetable oils industry and for matters connected therewith."

The motion was apopted.

RAO BIRENDRA SINGH : I introduce the Bill.

12.15 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Demand for Construction of a broad gauge Railway Line between Kottayam and Madurai.

SHRI SKARIAH THOMAS (Kottayam) : Sir, Kerala has a legitimate grievance that it has not received a fair share of railway development. The total kilometrage of railway line in Kerala is far below the national average, and this has created serious impediments in the economic development of the State. Kerala consists of three distinct geographical entities namely the highland, midland and the coastal region. The main railway line passes through the mid-regions and a large chunk of the population living in the highland do not have any rail facilities. It is this region which produces various cash crops which earn us valuable foreign/exchange. Thus, there is a long-standing demand that a Broad gauge line from Kottayam to Madurai should be constructed to cater to the needs of the people of this area. This railway line could touch important cash crops-producing areas like Ponkunnam, Kanjirappally, Mundakkyam, Peerumede, Kumali etc. and help the quick transportation of these crops. This line will bring about allround development of the state as it can give an impetus to the important commercial activities.

Therefore, I request the Railway Minister that in view of the inadequate railway facilities in Kerala a survey may immediately be undertaken to construct the Kottayam-Madurai broad gauge railway line.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Mohanlal Patel—Not here. Prof. Nirmala Kumari Shaktawat.

(ii) Need to provide barbed fencing around Army firing range at Pokharan

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र पोखरण की महत्वपूर्ण समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। पोखरण में सेना का चांदमारी क्षेत्र है जो सेना की निजी संपत्ति है पर यहां तारबंदी न होने से कई पशु तथा मनुष्य अकाल मौत मरते हैं।

भूखे प्यासे पशु तो पहुंचते ही हैं, इस क्षेत्र के मानव भी अपनी भूख मिटाने के लिए गोला बारूद के खाली खोके बीनने चले जाते हैं। चांदमारी क्षेत्र में पीतल के खाली खोके इकट्ठे करके यह 25 या 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कबाड़ी के यहां बेच देते हैं। जाने-अनजाने में जब कभी खाली गोला बारूद बीनते हुए कुछ बचा हुआ बारूद छूट जाने से वह मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं।

अतः सरकार से मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगी कि इस चांदमारी क्षेत्र की तारबंदी की जानी चाहिए।

गोला बारूद के खाली खोकों के धातु के टुकड़ों के लेन-देन को संगीन अपराध घोषित किया जाना चाहिए।